हिन्दी साप्ताहिक

R.N.I. No. UPHIN/2022/83621

जनता का सच

वर्ष 05 अंक 32 | लखनऊ शनिवार 15 अगस्त 2026 | पृष्ठ 04 मूल्य 2 रूपया

वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुलाया: अमित शाह

कांग्रेस की निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा

चित्तौड़गढ़/एजेंसी

केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर वंदे मातरम के अपमान का आरोप लगाते हुए कहा कि वोट बैंक के लालच में कांग्रेस ने वंदे मातरम को भुला दिया था। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 150वें वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने लाल किले से इस गीत को फिर से आयुष देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की निर्लज्जता देखिए, कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने को कहा। हम सब टीवी पर देखते रहे। 80 साल के बाद बंकिम बाबू का यह गान फिर से सम्मान प्राप्त कर रहा है, वो भी सोनिया गांधी को रास नहीं आ रहा है। अमित शाह रविवार को राजस्थान प्रवास के दौरान चित्तौड़गढ़ जिले के निंबाहेड़ा में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 21 फीट ऊंची अष्टधातु प्रतिमा के अनावरण के बाद आयोजित जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश की 140 करोड़ जनता सोनिया गांधी के इस कृत्य को देख रही है। वंदे मातरम का अपमान देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में यदि जरा भी शर्म बाकी है तो उसे हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा और देश की जनता से इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने राष्ट्र गौरव महाराणा प्रताप को श्रद्धापूर्वक नमन करते हुए कहा कि मेवाड़ की यह वीर भूमि देशभक्तों के लिए काशी से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वीर भूमि के महाराणा प्रताप, वीर पूंजा भील और सेठ भामाशाह की राष्ट्रभक्ति, धर्मभक्ति, स्वराज के प्रति लगन ने मुगलों के विजय रथ को रोक कर रख दिया था।

सीएम भजनलाल शर्मा ने राजस्थान की प्यास बुझाने का काम किया है: शाह

राजस्थान में जल संकट का उल्लेख करते हुए शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने तीन समझौतों के माध्यम से आधे राजस्थान की प्यास बुझाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा को जहां-जहां जनता का आशीर्वाद मिलता है, वहां पार्टी जनता की सेवा में जुट जाती है।राजस्थान में पहले 11 लाख घरों तक ही नल से पानी पहुंचा था। माताएं-बहनें सिर पर तीन-तीन मटकियां लेकर कोसों दूर से पानी लेकर आती थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुए जल जीवन मिशन से 8 साल में ही राजस्थान में 64 लाख घरों तक पानी पहुंचा है। गृह मंत्री ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी का पूरा जीवन राष्ट्र प्रथम की भावना को समर्पित रहा। वे बाल्यकाल से ही राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चले। 40 साल तक विपक्ष में रहने और हर प्रतिकूल परिस्थिति के बावजूद राष्ट्रभक्ति का सिद्धांत ही उनके जीवन का आधार रहा। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के विकास को लेकर कई बड़े फैसले किए। पूरे विश्व के दबाव के सामने ना झुकते हुए उन्होंने पोकरण में परमाणु परीक्षण किया।

गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए काम हुआ

गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए काम हुआ और स्वर्ण चतुर्भुज योजना के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार किया गया। उन्होंने कहा कि अटलजी ने जनजातीय विकास मंत्रालय बनाने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया। इसी का परिणाम है कि आज आदिवासी परिवार की बेटी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी देश के महान नेता थे। उनके कुशल नेतृत्व में द्वितीय परमाणु परीक्षण और 1999 के कारगिल युद्ध की जीत ने भारत की छवि को दुनियाभर में मजबूत किया।

मोदी ने सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के माध्यम से भारत को एक स्वाभिमानी और सशक्त राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाजपेयी जी के जन्मदिवस 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में घोषित किया। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सार्वजनिक जीवन राष्ट्र सेवा और समर्पण का प्रेरणादायी उदाहरण है। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाने और देश में नक्सलवाद की समस्या को खत्म करने में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही है। तीन नए आपराधिक कानून लागू कर उन्होंने देश की आपराधिक न्याय व्यवस्था में व्यापक सुधार किया है। देश में पहली बार गठित सहकारिता मंत्रालय उनके नेतृत्व में सहकारिता क्षेत्र में समृद्धि की प्रेरणादायक गाथा लिख रहा है। इस दौरान केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में चित्तौड़गढ़ समेत 15 जिलों में 5,659 करोड़ रुपये की लागत के 944 विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।

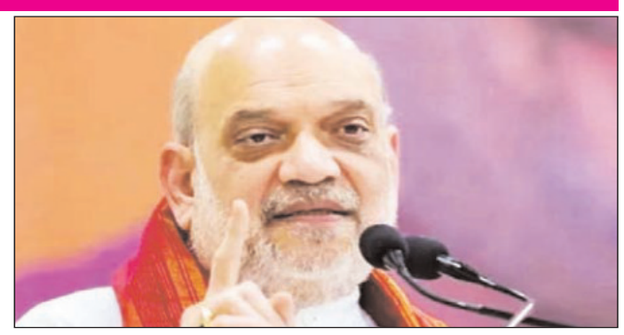

1,500 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल सुविधा की सौगात दी

1,500 गांवों को जल जीवन मिशन के तहत नल से जल सुविधा की सौगात दी। इससे पहले शाह ने सहकारिता विभाग एवं जिला प्रशासन की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। समारोह में उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा सहित अन्य मंत्री, सांसद, विधायक, स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। निंबाहेड़ा में जेके सर्किल पर मिनी अटल स्मारक में स्थापित वाजपेयी की प्रतिमा करीब चार हजार किलोग्राम अष्टधातु से बनी है। इसे आठ फीट ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थापित किया गया है। प्रतिमा जयपुर के कारीगरों ने तैयार की है।

स्मारक में दो अन्य प्लेटफॉर्म भी बनाए गए हैं, जिनमें एक पर वाजपेयी के प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुए पोकरण परमाणु परीक्षण की झलक और दूसरे पर उनके विभिन्न मुद्राओं में भाषण देते हुए चित्रण किया गया है।

100 अटल कैंटीन का संकल्प पूरा, पांच रुपये में मिलेगा 1 लाख लोगों को पौष्टिक भोजन

नई दिल्ली/एजेंसी

दिल्ली सरकार ने 100 अटल कैंटीन के संकल्प को रविवार को पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के तिमारपुर से 25 नई अटल कैंटीन के उद्घाटन के साथ आठ माह में पूरा कर लिया। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) ने अटल कैंटीन की शुरूआत 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर की थी। वर्तमान में इन 100 अटल कैंटीनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 1 लाख लोगों को भोजन उपलब्ध किया जा सकेगा। इस उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सांसद मनोज तिवारी, दिल्ली सरकार के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद, विधायक सूर्य प्रकाश खत्री सहित दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि दिल्ली में 100 अटल कैंटीनों का शुभारंभ अत्यंत सराहनीय पहल है, जिसका उद्देश्य गरीबों, झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों, श्रमिकों और दिल्ली में रोजगार के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों को सस्ता व पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह कोई सामान्य योजना नहीं, बल्कि समाज के सबसे जरूरतमंद वर्गों के प्रति संवेदनशीलता और सेवा-भाव का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि 'सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः' की भावना को साकार करते हुए दिल्ली सरकार ने 100 अटल कैंटीन स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया और आज यह संकल्प पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि 100 अटल कैंटीन का लक्ष्य पूरा होना दिल्ली सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह पहल श्रद्धेय अटलजी की अंत्योदय की भावना और जनसेवा के आदर्शों को समर्पित एक सार्थक श्रद्धांजलि भी है। अटलजी का जीवन समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के कल्याण और राष्ट्रसेवा के लिए समर्पित रहा। उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाते हुए दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति सम्मानजनक और पौष्टिक भोजन से वंचित न रहे।

डिग्री के साथ अनुशासन, आचरण भी जरूरी: उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन

चेंगलपट्टू/एजेंसी

चेंगलपट्टू जिले के कट्टांकुलत्तूर स्थित एसआरएम विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित 22वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान कीं। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ अनुशासन, अच्छे आचरण और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने तथा व्यक्तिगत सफलता के साथ देश के विकास में योगदान देने का आह्वान किया। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज डिग्री प्राप्त कर रहे विद्यार्थी इस बात का प्रमाण हैं कि विकसित भारत का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दीक्षांत समारोह केवल डिग्री प्राप्त करने का अवसर नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के अनुशासन, कार्यशैली और जीवन के प्रति समग्र दृष्टिकोण का भी महत्वपूर्ण पड़ाव है। कोरोना महामारी के दौरान भारत की भूमिका का उल्लेख करते हुए सी.पी. राधाकृष्णन ने कहा कि भारत में निर्मित दवाएं दुनिया के विभिन्न देशों तक पहुंचीं। महामारी के दौरान भारत के दवा उत्पादन और चिकित्सा क्षेत्र के योगदान की कई देशों ने सराहना की। उन्होंने कहा कि हाल ही में केन्या की संसद ने भी भारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। भारत ने महामारी के दौरान न केवल अपने नागरिकों की जरूरतें पूरी कीं, बल्कि विभिन्न देशों को भी आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराईं।

'भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में तेजी से उभर रहा'

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने भारत दुनिया की प्रमुख आर्थिक शक्तियों में तेजी से उभर रहा है। आर्थिक रूप से चौथे स्थान पर स्थित भारत जल्द ही तीसरे स्थान की ओर बढ़ रहा है। देश को भविष्य में दुनिया की अग्रणी आर्थिक शक्ति बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद देश में तकनीकी शिक्षा संस्थानों, विश्वविद्यालयों और एम्स जैसे चिकित्सा संस्थानों समेत शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ है। देश के विकास और भविष्य के निर्माण में युवाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपनी व्यक्तिगत प्रगति तक सीमित न रहें, बल्कि देश के विकास में भी सक्रिय योगदान दें। उन्होंने कहा कि पाठ्यक्रम के माध्यम से प्राप्त शिक्षा विद्यार्थियों को डिग्री दिला सकती है, लेकिन जीवन में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए शिक्षा के साथ अनुशासन, अच्छा आचरण और जिम्मेदारी की भावना भी जरूरी है।

सी.पी. राधाकृष्णन ने युवाओं को शराब और नशीले पदार्थों से पूरी तरह दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि कॉलेज विद्यार्थियों के बीच नशीले पदार्थों के सेवन से जुड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। नशा युवाओं के भविष्य के लिए किसी भी रूप में लाभदायक नहीं है और इससे स्वास्थ्य एवं जीवन पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत

कोलकाता/एजेंसी

पश्चिम बंगाल में केंद्र की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (पीएम-जेएवाई) के लागू होने की औपचारिक शुरूआत रविवार को कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम से हुई। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री जगत प्रकाश नड्डा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे।

जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की। पश्चिम बंगाल के लिए यह स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है।

केंद्र सरकार के अनुसार, राज्य अब आयुष्मान भारत पीएम-जेएवाइ लागू करने वाला देश का 36वां राज्य/केंद्रशासित प्रदेश बन गया है। योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे गंभीर बीमारियों और अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में परिवारों पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा। कार्यक्रम से पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि राज्य में पहले से स्वास्थ्य साथी योजना के दायरे में आने वाले बड़ी संख्या में लाभार्थियों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया था कि आयुष्मान भारत के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और चरणबद्ध तरीके से लाभार्थियों को कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

भारतीय रेल ने पेयजल व्यवस्था में सुधार के दिए निर्देश

नई दिल्ली/एजेंसी

भारतीय रेल ने सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए देशभर में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत करीब 20,000 स्थानों पर नया ह्यटैंक टू टैपह्ल जल फिल्टरेशन सिस्टम और व्यापक जल फिल्टरेशन एवं निगरानी व्यवस्था स्थापित की जाएगी। पानी की टंकियों को भी बदला जाएगा। रेल मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार सीएजी की रिपोर्ट के बाद रविवार को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीआरबी एवं सीईओ और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की दिनभर समीक्षा बैठक चली। समीक्षा में सुरक्षित पेयजल के लिए तत्काल सुधारात्मक उपायों के आदेश दिए गए। रेलवे के पूरे नेटवर्क में करीब 20 हजार स्थानों पर जल फिल्टरेशन और निगरानी प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

निर्देशों के तहत पानी की गुणवत्ता की नियमित जांच अनिवार्य होगी। स्रोत और आउटलेट स्थानों पर नियमित जल गुणवत्ता परीक्षण किया जाएगा। केंद्रीकृत निगरानी और जवाबदेही की व्यवस्था लागू होगी।

फर्जी और भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट से निपटने की तैयारी

नई दिल्ली/एजेंसी

आज के डिजिटल दौर में सोलह मीडिया पर सच्चाई से कोसों दूर, तोड़-मरोड़ कर पेश की गई और भ्रामक सामग्री का प्रसार तेजी से चिंता का विषय बनता जा रहा है। इसी चुनौती से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों ने कमर कस ली है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, जनता तक सही और प्रामाणिक जानकारी समय पर पहुंचाने के लिए विभागों में क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) का गठन किया जा रहा है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की तुरंत पहचान करना, उनकी सूक्ष्मता से जांच करना और तथ्यों के साथ उनका त्वरित खंडन करना है। वर्तमान में बिजली, कृषि और वाणिज्य जैसे कई प्रमुख मंत्रालयों और विभागों ने इन विशेष टीमों का गठन भी कर लिया है। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी भ्रामक पोस्ट पर संज्ञान लेते ही संबंधित मंत्रालय की ओर से उसका सटीक जवाब दो घंटे के भीतर दिया जाना चाहिए ताकि जनता के बीच किसी भी प्रकार की भ्रम की स्थिति या गलतफहमी पैदा न हो सके। त्वरित और पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था इन टीमों के कार्यक्षेत्र में सोशल मीडिया पर विभाग की नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों और फैसलों से जुड़े हर कंटेंट की नियमित निगरानी करना शामिल है

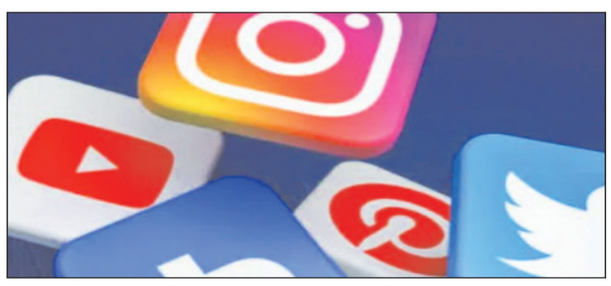

वंदे मातरम् को लेकर सोनिया-राहुल के खिलाफ शिकायत

नई दिल्ली। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के गायन को लेकर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के कथित आचरण पर शिकायत दी गई है। शिकायतकर्ता ने दोनों के खिलाफ मामले की निष्पक्ष जांच कराने और कानून लागू होने की स्थिति में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। शिकायत के अनुसार, 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित किया गया था। समारोह में ह्यवंदे मातरमह्ल का गायन हो रहा था। आरोप है कि गायन के दौरान सोनिया गांधी वहां मौजूद थीं और गीत के शुरूआती हिस्से के बाद उन्होंने उपस्थित लोगों की ओर कुछ इशारे किए तथा बातचीत की।

पंजाब के किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर लगाया पक्का मोर्चा

चंडीगढ़/एजेंसी

हरियाणा के जींद जिले से सटे पंजाब के खनौरी-दाता सिंह वाला बॉर्डर पर रविवार को दिन भर तनाव की स्थिति बनी रही। पंजाब के किसान संगठनों द्वारा दिल्ली कूच का ऐलान किए जाने के बाद हरियाणा पुलिस ने सडक पर बेरिकेडिंग करके रास्ता जाम कर दिया। जींद की जिला उपायुक्त के साथ दो बार हुई बैठकों का जब कोई परिणाम नहीं निकला तो देर शाम किसानों ने खनौरी बॉर्डर पर पक्का मोर्चा लगाने का ऐलान कर दिया। पंजाब के विभिन्न किसान संगठनों ने रविवार को दिल्ली कूच का ऐलान किया था। किसान संगठन पैदल यात्रा करके 29 अगस्त को दिल्ली पहुंचने का दावा कर रहे हैं। जिसके चलते पंजाब के विभिन्न जिलों से किसान बसों में भरकर खनौरी बॉर्डर पर पहुंचे।

रविवार सुबह से ही पुलिस ने हरियाणा की सीमा को सील कर दिया और तीन लेयर की बेरिकेडिंग की। पंजाब से दिल्ली जा रहे 55 किसानों को खनौरी-दाता सिंहवाला बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस ने रोक दिया है। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के नेतृत्व में 55 किसानों के जत्थे ने 2024 के किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण सिंह की मौत वाले स्थान से मिट्टी उठाई। डल्लेवाल ने कहा कि अब रास्ता किसानों ने नहीं, हरियाणा पुलिस ने रोका है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। थोड़ी संख्या में किसान दिल्ली जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक किसान यहां से नहीं हटेंगे। रकिसानों ने कहा कि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगी। इसका उद्देश्य किसानों से जुड़े मुद्दों के साथ अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील के विरोध की आवाज केंद्र सरकार तक पहुंचाना है। किसान नेताओं ने बताया कि यात्रा में एक किसान मुख्य रूप से पैदल चलेगा, जबकि उसके साथ कुछ किसान रहेंगे, जो उसका सामान उठाएंगे। रास्ते में जगह-जगह पड़ाव होंगे और जत्था चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ेगा।

लक्ष्य 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर-मंतर पहुंचने का है। वहां एक दिन की किसान पंचायत आयोजित की जाएगी। इसके बाद सरकार को किसानों की मांगों से संबंधित मांग पत्र सौंपने का प्रयास किया जाएगा।

संपादकीय

बोफोर्स कांड: एक झूठ के शापित होने का सच

एक झूठ के बल पर खड़ा हुआ बोफोर्स कांड सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद अब फाइलों में बंद हो गया। केस चालिस साल चला। इस पर 250 करोड़ रुपए व्यय हुए। इतना सब होने और चालिस साल की जीतोड़ कवायद के बाद भी बोफार्स खरीद में रिश्वत लेने की सच्चाई सामने नही आई। केस तो खत्म हो गया किंतु यह तै नही हो पाया कि इस प्रकरण में रिश्वत ली गई या नहीं । कोर्ट के केस खारिज करने के बाद भी रिशवत लेने का आरोप आज भी अपनी जगह खड़ा है।इस कांड का पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी एवं अन्य आरोपियों के माथे पर लगा बेइमानी का दाग कभी खत्म नही हो पाएगा? क्या उनके परिवार माथे पर लगे इस कलंक से मुक्त हो पाएंगे? क्या उनके परिवार के सम्मान की हुई क्षति की कभी पूर्ति हो सकेगी? पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह के बार -बार बोले जाने वाले बोफोर्स खारीद में रिश्वत ने जनता के मन में तक जमाये झूठ के कारण राजीव गांधी से जनता दूर हो गई और उन्हें अपनी सरकार तक गंवानी पड़ी ।

सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स को बरी करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के 2005 के फैसले के खिलाफ दायर अंतिम अपील को भी खारिज कर दिया है। इसके साथ ही भारत के सबसे चर्चित और लंबे समय तक चलने वाले भ्रष्टाचार के मामलों में से एक बोफोर्स कांड का कानूनी अध्याय हमेशा के लिए बंद हो गया है।

मामले में जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विनोद के. चंद्रन की बेंच ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता की स्थगन की मांग को ठुकराते हुए मामले की आखिरी याचिका को खारिज कर दिया। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने भी इस मामले में अपील की थी। इस अपील को भी सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में ही देरी के आधार पर खारिज कर दिया था। 1986 में हुए इस रक्षा सौदे का विवाद लगभग 40 साल तक अदालतों और भारतीय राजनीति के केंद्र में रहा और अंत में समाप्त हो गया।

पूरा मामला 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडिश कंपनी एबी बोफोर्स के बीच हुए 1,437 करोड़ रुपये के उस समझौते से जुड़ा है। इसके तहत भारतीय सेना के लिए 400 हॉवित्जर तोपें खरीदी जानी थीं। साल 1987 में स्वीडिश रेडियो ने यह सनसनीखेज खुलासा किया कि इस सौदे को हासिल करने के लिए भारतीय राजनेताओं और रक्षा अधिकारियों को अवैध कमीशन दिए गए थे। इस खुलासे ने भारतीय राजनीति में तहलका मचा दिया था।

कांग्रेस छोड़ने के बाद, विश्वनाथ प्रताप (वीपी) सिंह ने खुद को एक ह्यईमानदार नेताह्न (मिस्टर क्लीन) के रूप में स्थापित किया। उन्होंने राष्ट्रीय मोर्चा (जनता दल) का गठन किया। 1989 के लोकसभा चुनाव अभियान के दौरान वीपी सिंह अपनी रैलियों में बेहद आक्रामक रहे। वह अक्सर मंचों से अपनी जेब से एक सफेद पर्ची निकालकर लहराते थे। उनका दावा था कि उस पर्ची पर बोफोर्स घोटाले के पुख्ता सबूत, दलाली की रकम पाने वालों के नाम और राजीव गांधी के कथित स्विस बैंक खातों के नंबर लिखे हैं। कथित स्विस बैंक खातों के नंबर लिखे हैं। इस आक्रामक अभियान ने जनता के बीच राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा किया। बोफोर्स घोटाले को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर वीपी सिंह ने विपक्ष को एकजुट किया। इस आक्रामक अभियान ने जनता के बीच राजीव गांधी सरकार के खिलाफ भारी आक्रोश पैदा किया। उनकी बेइंतहा छवी खराब की। राजीव गांधी सरकार पर गंभीर सवाल उठे और 1989 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार का इसे एक बड़ा कारण माना गया। प्रधानमंत्री बनते ही वीपी सिंह ने बोफोर्स कंपनी पर भारत के साथ भविष्य के किसी भी रक्षा सौदे के लिए प्रतिबंध लगा दिया। उन्होंने मामले की जांच के लिए अधिकारियों की एक विशेष टीम भी गठित की।

भारी वादों और दावों के बावजूद, झूठ के बल पर बनी वीपी सिंह की सरकार केवल 11 महीने चली। सकार बनने के बाद वीपी सिंह 11 महीने की आपनी सरकार के कार्यकाल में कोई भी सबेत नही दे सके। स्विस बैंक का खाता भी नही बता पाए। ये सरकार राजीव गांधी के खिलाफ सीधे तौर पर कोई ठोस कानूनी सबूत पेश नहीं कर सकी। आलोचकों का कहना है कि चुनावी रैलियों में जिस पर्ची का दावा किया गया था, उसका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आ सका।

विदेशी चंदे पर नियंत्रण और संतुलन की अपेक्षा

12 अगस्त 2026 का दिन भारतीय संसद के लिए इसलिए महत्वपूर्ण रहा कि विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 यानी एफसीआरए विधेयक को लोकसभा ने 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति-जेपीसी के पास भेज दिया। यह फैसला केवल एक विधेयक को संसदीय प्रक्रिया के अगले चरण में भेजना नहीं है, बल्कि उस व्यापक बहस का अवसर है जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी धन की पारदर्शिता, धार्मिक एवं सामाजिक संस्थाओं की स्वायत्तता, नागरिक समाज की भूमिका और लोकतांत्रिक अधिकार-सभी एक साथ जुड़े हुए हैं। विधेयक को जेपीसी के पास भेजे जाने से सरकार और विपक्ष के बीच तत्काल टकराव को कुछ हद तक विमर्श में बदलने का अवसर मिला है। एफसीआरए का इतिहास भी इस बहस की गंभीरता को समझने में मदद करता है। विदेशी धन के माध्यम से देश के राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर बाहरी प्रभाव की आशंकाओं को देखते हुए 1976 में पहली बार कानून बनाया गया था। वर्ष 2010 में इसे नए एफसीआरए कानून से प्रतिस्थापित किया गया और उसके बाद 2020 सहित विभिन्न चरणों में इसके प्रावधान अधिक कठोर होते गए। आज यह कानून केवल विदेशी चंदे की प्राप्ति और उसके उपयोग का लेखा-जोखा रखने का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े विमर्श का भी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

आंकड़े इस विषय की व्यापकता बताते हैं। पीआरएस के अनुसार 15 जुलाई 2026 तक 14,449 एफसीआरए प्रमाणपत्र सक्रिय थे, जबकि 22,498 रद्द और 15,212 समाप्त माने गए। 2019 से 2022 के बीच 13,520 संगठनों को लगभग 55,741 करोड़ रुपये का विदेशी अंशदान मिला। इन आंकड़ों को देखकर यह सवाल स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी धनराशि का उपयोग कहां, किस उद्देश्य से और किस स्तर की निगरानी के साथ हुआ? लेकिन इसके साथ दूसरा प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है-क्या किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त हो जाना अपने आप में किसी वित्तीय या आपराधिक अनियमितता का प्रमाण माना जा सकता है? सरकार के अपने स्पष्टीकरण के अनुसार भी पंजीकरण समाप्त होने के कई कारण हो सकते हैं और हर समाप्ति को गलत काम से जोड़ना उचित नहीं है। यहीं से प्रस्तावित संशोधन का सबसे संवेदनशील पक्ष सामने आता है। विधेयक में ह्यनामित प्राधिकरणह्न की व्यवस्था प्रस्तावित है। यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण रद्द हो जाता है, वह स्वयं पंजीकरण छोड़ देती है या उसका प्रमाणपत्र नवीनीकरण न होने के कारण समाप्त हो जाता है, तो विदेशी अंशदान और उससे निर्मित संपत्तियां पहले अस्थायी रूप से इस प्राधिकरण के अधीन आ सकती हैं। यदि निर्धारित अवधि में पंजीकरण बहाल नहीं होता तो संपत्तियां स्थायी रूप से निहित की जा सकती हैं तथा उन्हें सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए उपयोग या बेचने का प्रावधान है। बिक्री से प्राप्त राशि और अप्रयुक्त विदेशी अंशदान भारत की समेकित निधि में जमा किए जाने का प्रस्ताव है।

भारत में समय-समय पर ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें विदेशी वित्तपोषण के दुरुपयोग, वित्तीय अनियमितताओं अथवा राष्ट्रीय हित से टकराने वाली गतिविधियों को लेकर सवाल उठे हैं। इसलिए एफसीआरए का मूल उद्देश्य-विदेशी अंशदान को पारदर्शी, उत्तरदायी और वैध उद्देश्यों तक सीमित रखना-न तो अनुचित है और न ही लोकतंत्र विरोधी।

लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा की आवश्यकता और प्रशासनिक शक्ति के विस्तार के बीच एक स्पष्ट रेखा भी होनी चाहिए।

प्रधान मंत्री का लालकिले से विकसित भारत का संकल्प

अशोक भाटिया

ऐतिहासिक लालकिले की प्राचीर केवल पत्थरों की एक संरचना नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र भारत के उतार-चढ़ाव, उसकी आकांक्षाओं, उसकी नियति और उसके सामूहिक संकल्पों की मूक गवाह रही है। हर वर्ष 15 अगस्त को इस प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं, तो वह केवल एक औपचारिक भाषण नहीं होता, बल्कि वह आने वाले समय के लिए देश का नीतिगत और वैचारिक रोडमैप होता है। स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी ऐतिहासिक प्राचीर से वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो अटूट संकल्प दोहराया है, वह देश की समकालीन राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के लिए एक युगांतकारी मोड़ है। विकसित भारत का यह विजन महज एक राजनीतिक नारा नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ नागरिकों की सामूहिक चेतना को जगाने और उन्हें राष्ट्र निर्माण के एक महायज्ञ में आहुति देने के लिए प्रेरित करने वाला एक व्यापक राष्ट्रीय दर्शन है। जब हम इस विराट संकल्प की बात करते हैं, तो हमें इसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रासंगिकता को गहराई से समझना होगा। भारत ने लगभग दो सदियों तक औपनिवेशिक दासता और आर्थिक शोषण का दंश झेला है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ, तब हमारी अर्थव्यवस्था जर्जर थी, साक्षरता दर दयनीय थी और अकाल तथा गरीबी जैसी बुनियादी चुनौतियां हमारे सामने थीं। शुरूआती दशकों में भारत का मुख्य ध्यान आत्मनिर्भरता और बुनियादी अस्तित्व की रक्षा पर था। हमने खाद्यान्न संकट से निपटने के लिए हरित क्रांति की, अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सैन्य तंत्र को मजबूत किया और धीरे-धीरे एक ठोस औद्योगिक आधार तैयार किया। आज, स्वतंत्रता के इस दौर में, भारत उस स्थिति से बहुत आगे निकल चुका है और अब हम केवल एक अस्तित्व बनाए रखने वाले देश नहीं हैं, बल्कि हम वैश्विक पटल पर एक नई दिशा तय करने वाले राष्ट्र बन चुके हैं। यह संकल्प इस बात का प्रतीक है कि अब भारत अपनी विकासशील छवि के खोल को तोड़कर वैश्विक शक्तियों की अग्रिम पंक्ति में खड़े होने के लिए पूरी तरह तैयार है। 2047 का वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारी स्वतंत्रता का शताब्दी वर्ष होगा, और कोई भी राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर दुनिया के सामने अपनी सफलता का क्या प्रमाण प्रस्तुत करता है, यही उसका वास्तविक ऐतिहासिक मूल्यांकन होता है।

इस व्यापक संकल्प को धरातल पर उतारने के लिए देश के चार प्रमुख वर्गों को विकास का मुख्य केंद्र बिंदु बनाया गया है, जिन्हें युवा, महिला, किसान और गरीब के रूप में रेखांकित किया गया है। इन चारों स्तंभों के समग्र सशक्तिकरण के बिना किसी भी विकसित समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। भारत आज दुनिया का सबसे युवा देश है और हमारी जनसांख्यिकीय लाभांश हमारी सबसे बड़ी ताकत है। विकसित भारत का सपना तभी सच हो सकता है जब इस युवा ऊर्जा को सही दिशा, उत्कृष्ट शिक्षा और वैश्विक स्तर का कौशल मिले। देश में स्टार्टअप इकोसिस्टम का तेजी से विस्तार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना इसी दिशा में उठाए गए बड़े कदम हैं। इसके साथ ही, विकसित भारत का दूसरा अनिवार्य पहलू महिलाओं का सशक्तिकरण और उनके नेतृत्व में होने वाला विकास है। जब तक देश की आधी आबादी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह सक्रिय नहीं होगी, तब तक विकास की रफ्तार अधूरी रहेगी। सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती महिलाओं की बढ़ती संख्या इस बात का प्रमाण है कि वे अब नीति निर्धारण के केंद्र में आ रही हैं। इसी तरह, भारत की आत्मा आज भी गांवों में बसती है और हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार, आधुनिक खेती को बढ़ावा और वैश्विक कृषि आपूर्ति श्रृंखला में भारत की हिस्सेदारी बढ़ाना आवश्यक है। किसान जब पारंपरिक खेती से आगे बढ़कर आधुनिक कृषि-उद्यमी बनेगा, तभी ग्रामीण भारत समृद्ध होगा। अंत में, अंत्योदय की भावना के अनुरूप समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचना चाहिए, क्योंकि किसी भी राष्ट्र को तब तक विकसित नहीं कहा जा सकता जब तक कि बहुआयामी गरीबी का पूरी तरह उन्मूलन न हो जाए और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन स्तर न मिल जाए।

आर्थिक मोर्चे पर, भारत आज दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और शीर्ष वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की ओर अग्रसर है। लेकिन विकसित देश बनने के लिए हमें केवल सकल घरेलू उत्पाद के आकार को ही नहीं बढ़ाना है, बल्कि प्रति व्यक्ति आय और नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में भी गुणात्मक सुधार करना होगा। इसके लिए विनिर्माण और आत्मनिर्भरता पर विशेष बल देना आवश्यक है। मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत आज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। रक्षा क्षेत्र में, जहां कभी हम पूरी तरह आयातों पर निर्भर थे, आज हम स्वदेशी अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का निर्माण कर रहे हैं और उनका निर्यात भी बढ़ा रहे हैं। भारतीय कॉर्पोरेट जगत को अब वैश्विक कंपनियों की तर्ज पर अपनी क्षमता का विस्तार करना होगा ताकि भारतीय ब्रांड दुनिया भर के बाजारों में अग्रणी भूमिका निभा सकें। इसके साथ ही, देश के बुनियादी ढांचे का कायाकल्प किया जा रहा है। आधुनिक रेलवे, एक्सप्रेसवे का विस्तृत नेटवर्क, जलमार्गों का विकास और हवाई अड्डों का आधुनिकीकरण देश की लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने और व्यापार को सुगम बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। एक मजबूत और आधुनिक बुनियादी ढांचा ही विकसित भारत की ठोस नींव बनेगा, जो देश के औद्योगिक विकास को नई गति प्रदान करेगा।

तकनीक और नवाचार के इस युग में जो देश अग्रणी रहेगा, वही दुनिया के भविष्य को दिशा देगा। भारत ने डिजिटल क्षेत्र में जो क्रांति की है, उसने दुनिया के विकसित देशों को भी अचंभित किया है। हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल लेनदेन की व्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर एक मिसाल बन चुकी है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह केवल तकनीक का उपभोक्ता नहीं है, बल्कि वह विश्व को सस्ती, सुरक्षित और समावेशी तकनीक देने वाला प्रदाता भी है। विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में बढ़ता निवेश इस विजन को और स्पष्ट करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर मिशन, क्वांटम कंप्यूटिंग, अंतरिक्ष अनुसंधान और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में भारत का बढ़ता कदम यह दशार्ता है कि हम भविष्य की तकनीकों के मामले में दुनिया के अग्रणी देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर और संप्रभु होना विकसित भारत की एक अनिवार्य शर्त है, जो हमें वैश्विक मंच पर एक अद्वितीय पहचान दिलाएगी।

संकल्प जितना विराट होता है, उसकी राह की चुनौतियां भी उतनी ही कठिन होती हैं। विकसित भारत के मार्ग में कई आंतरिक और बा चुनौतियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की आर्थिक प्रगति के साथ-साथ क्षेत्रीय और सामाजिक असमानता को पाटना एक बड़ी चुनौती है।

विकास का लाभ समाज के हर वर्ग और देश के हर कोने तक समान रूप से पहुंचना चाहिए। इसके अलावा, भारत को पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास के बीच एक कुशल संतुलन बनाना होगा। जलवायु परिवर्तन के खतरों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना युद्धस्तर पर आवश्यक है। प्रशासनिक स्तर पर, हमारी व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और नागरिक-अनुकूल बनना होगा, क्योंकि लालफीताशाही और भ्रष्टाचार विकास की गति को धीमा करते हैं। वैश्विक मोर्चे पर, वर्तमान समय की भू-राजनीतिक अस्थिरता और आर्थिक व्यवधान भी हमारे सामने चुनौतियां खड़ी करते हैं, जिनसे निपटने के लिए भारत को अपनी कूटनीतिक कुशलता और आंतरिक आर्थिक सुदृढ़ता को निरंतर मजबूत बनाए रखना होगा।

उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा मानसून सत्र

ललित गर्ग

संसदीय मयार्दाओं का क्षरण कब तक? आखिर कब हम संसद के एक-एक मिनट का उपयोग करने की पात्रता विकसित करेंगे? आजादी की 80वीं वर्षगांठ की आयोजना से पूर्व भारत में संसद का मानसून सत्र जिस निराशाजनक स्थिति, नाउम्मीदी और उपेक्षापूर्ण स्थितियां के साथ संपन्न हुआ, वह केवल किसी एक दल, सरकार या विपक्ष की विफलता नहीं है, बल्कि हमारी संसदीय संस्कृति के सामने खड़ा एक गंभीर प्रश्नचिह्न है। 25 दिनों तक चले इस सत्र में तीखी राजनीतिक बहस के बजाय हंगामा, नारेबाजी, गतिरोध और कार्यवाही बाधित करने की प्रवृत्ति अधिक प्रभावी रही। प्रश्न यह नहीं है कि सत्ता पक्ष सही था या विपक्ष, प्रश्न यह है कि क्या हमारी संसद अपने मूल दायित्व-जनता के प्रश्नों पर गंभीर विमर्श, सरकार की जवाबदेही और राष्ट्रहित में कानून निर्माण को पूरा कर पा रही है? इस सत्र के आंकड़े स्वयं बहुत कुछ कह रहे हैं। लोकसभा की उत्पादकता बमुश्किल 19 प्रतिशत रही, जबकि राज्यसभा में लगभग 39 प्रतिशत काम हो पाया। लोकसभा में एक भी दिन प्रश्नकाल पूरा नहीं हो सका। यह स्थिति इसलिए अधिक चिंताजनक है क्योंकि प्रश्नकाल संसद की आत्मा माना जाता है। देश की जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को सरकार से प्रश्न पूछने और सरकार को उनका उत्तर देने का अवसर ही यदि सदन में उपलब्ध न हो, तो लोकतंत्र की जवाबदेही किस रास्ते से सुनिश्चित होगी? 28 जुलाई को लोकसभा में अपेक्षाकृत ठीक काम हुआ, जबकि राज्यसभा में भी केवल कुछ दिन ही सार्थक कार्यवाही हो सकी। शेष समय का बड़ा हिस्सा राजनीतिक टकराव की भेंट चढ़ गया।

संसद केवल ईंट-पत्थर से बनी इमारत नहीं है। वह भारत की सामूहिक चेतना का सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच है। वहां देश के करोड़ों नागरिकों की आकांक्षाएं, समस्याएं और सपने पहुंचते हैं। किसान, मजदूर, विद्यार्थी, महिला, व्यापारी, युवा, गरीब और वंचित वर्ग-सभी की आवाज संसद के माध्यम से राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बनती है। इसलिए संसद का एक मिनट भी केवल सांसद का समय नहीं होता, वह देश की जनता के धन, विश्वास और लोकतांत्रिक अधिकार का समय होता है। संसद का प्रत्येक व्यर्थ गया मिनट वास्तव में जनता के विश्वास से घटा हुआ एक मिनट है। दुर्भाग्य यह है कि संसद में हंगामा अब अपवाद नहीं, बल्कि संसदीय राजनीति का लगभग नियमित हथियार बनता जा रहा है। मुद्दे उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, सरकार को घेरना विपक्ष का दायित्व है और असहमति लोकतंत्र की शक्ति है, लेकिन असहमति को संवाद में बदलने के बजाय कार्यवाही रोक देना लोकतंत्र को मजबूत नहीं करता। विरोध की भी एक मयार्दा होती है। यदि विपक्ष अपनी बात रखने के लिए सदन को चलने ही न दे और सत्ता पक्ष विपक्ष की आवाज सुनने की बजाय राजनीतिक बहुमत को ही पर्याप्त समझे, तो दोनों मिलकर संसदीय लोकतंत्र की आत्मा को कमजोर करते हैं।

इस सत्र में कुछ घटनाएं इस गिरावट को और स्पष्ट करती हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने सत्र के समापन पर पारंपरिक समापन भाषण नहीं दिया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस द्वारा लोकसभा अध्यक्ष के साथ होने वाली चाय पार्टी का बहिष्कार किया जाना भी केवल एक कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं माना जा सकता। यह सदन के भीतर बढ़ती राजनीतिक कटुता का संकेत है। लोकतंत्र में मतभेद स्वाभाविक हैं, मनभेद लोकतंत्र के लिए घातक हैं। संसद में बहस के बाद हाथ मिलाने की संस्कृति विकसित होनी चाहिए, बहस के बाद दूरी बढ़ाने की नहीं। इस मानसून सत्र को नीट-यूजी पेपर लीक, जंतर-मंतर छात्र आंदोलन, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग और राम मंदिर में दान चोरी जैसे मुद्दों के लिए भी याद किया जाएगा। जंतर-मंतर पर हुई हिंसा के बाद विपक्ष केंद्रीय गृहमंत्री से जवाब मांग रहा था। जब सत्र के अंतिम दिनों में गृहमंत्री जवाब देने को तैयार हुए तो विपक्ष द्वारा उनका वक्तव्य सुनने से इनकार करना संसदीय विवेक की कसौटी पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। यदि विपक्ष को सरकार के जवाब से असहमति थी, तो उसे सुनकर तथ्यात्मक प्रतिवाद करना अधिक प्रभावी लोकतांत्रिक रास्ता होता। संसद में जवाब सुनने से इनकार करना प्रश्न का समाधान नहीं, प्रश्न को अनुत्तरित छोड़ना है।

यह भी सच है कि तमाम गतिरोध के बीच संसद ने कुछ महत्वपूर्ण काम किए। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक यानी एफसीआरए को सरकार ने विरोध के बीच संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026 दोनों सदनों में पारित हुआ, जिसका उद्देश्य परीक्षाओं में अनुचित साधनों पर अंकुश लगाना और दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बैंकिंग रिकॉर्ड को नए डिजिटल ढांचे से जोड़ने, जन्म-मृत्यु के विलंबित पंजीकरण को अधिक कठोर बनाने तथा अन्य विधायी एवं प्रशासनिक सुधारों की दिशा में भी कदम उठे। केरल का नाम विधिवत केरलम किए जाने का निर्णय भी इसी सत्र का हिस्सा रहा। ये उपलब्धियां बताती हैं कि यदि संसद चले तो कम समय में भी महत्वपूर्ण काम संभव है। लेकिन सवाल फिर वही है-जब संसद चल सकती है तो उसे बार-बार रोकने

जंतर मंतर-रांची : छात्र आंदोलन एक रूप अनेक

निर्मल रानी

देश इन दिनों लगभग राष्ट्रव्यापी छात्र आक्रोश व आंदोलन से रूबरू है। अभी कुछ दिन पहले ही NEET पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई धांधली के खिलाफ 6 जून से शुरू होकर 25 जुलाई 2026 तक चला आंदोलन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद खत्म हुआ था। इसके बाद ही झारखंड में भी जेपीएससी (JPSC) और जेएसएससी (JSSC) परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के विरुद्ध 29 जुलाई से रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र आंदोलन की शुरूआत हुई। यहाँ भी छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता, धांधली और अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच आदि मांगों को लेकर धरना, प्रदर्शन और विधानसभा घेराव जैसे कार्यक्रम कर रहे हैं। परन्तु कुछ दिनों पूर्व हुये दिल्ली के जंतर-मंतर व वर्तमान समय रांची में चल रहे छात्र आंदोलन में जहां कुछ बातें समान हैं वहीं कई बातें विरोधाभासी भी हैं। उदाहरण के तौर पर दोनों ही आंदोलन पेपर लीक और राष्ट्रीय परीक्षाओं में हुई धांधली व अनियमितताओं के खिलाफ किये गए हैं। जंतर मंतर की ही तरह रांची में भी जहाँ आंदोलनस्थल पर अनेक स्वयंसेवी लंगर चला रहे हैं व आंदोलनकारी छात्रों के दूर दराज बैठे समर्थक फूड ऐप्स के जरिए सीधे आंदोलन स्थल पर भोजन ऑर्डर कर रहे हैं व छात्रों को मेडिकल व अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। यहाँ भी भोजन इतनी अधिक मात्रा में आ रहा है कि आंदोलनकारी छात्रों ने वीडियो जारी कर लोगों से कुछ दिन ऑर्डर रोकने की अपील की ताकि खाना बर्बाद न हो और बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों में बांटा जा सके। इसके अलावा रांची के स्थानीय दुकानदारों और आम नागरिकों द्वारा आंदोलन स्थल पर भोजन,समोसे, बिरयानी,नाश्ता और पानी आदि पहुंचाया जा रहा है। अनशन पर बैठे छात्र नेताओं की सेहत की देखभाल के लिए रांची के सदर अस्पताल में मेडिकल टीम नियमित रूप से आंदोलन स्थल पर पहुंचकर स्वास्थ्य जांच (ब्लड प्रेशर, शुगर लेवल) कर रही है। इसके अतिरिक्त झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने निर्देश जारी किया है कि आंदोलन के दौरान बीमार या चोटिल होने वाले छात्रों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी, चाहे वे सरकारी अस्पताल में इलाज कराएं या निजी अस्पताल में।

परन्तु इन दोनों अर्थात दिल्ली व रांची के आंदोलन में जो सबसे बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है वह है जंतर मंतर के छात्र आंदोलन का विरोध करने वालों का रांची के आंदोलन में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना। बड़ी हैरत की बात है कि जो वर्ग,जो संगठन और जिस विचारधारा से जुड़े लोग जंतर मंतर के आंदोलनकारियों को देशद्रोही, बदतमीज, गटर जनरेशन,गलियां बोलने व अपशब्द इस्तेमाल करने वालों का झुण्ड,विदेशी फंडिंग से चलने वाला आंदोलन बता रहे थे, दिल्ली के आंदोलन में जो लोग हिन्दू-मुस्लिम का दृष्टिकोण ढूंढ रहे थे,जिन्हें दिल्ली के आंदोलन कारी आवारा व चरित्रहीन नजर आ रहे थे वही लोग वही वर्ग और वही विचारधारा रांची के छात्र आंदोलन में कुछ इसतरह बढ़चढ़कर हिस्सा लेने को उतावली है गोया रांची का आंदोलन छात्र आंदोलन के बजाये देश का दूसरा स्वाधीनता संग्राम हो?

याद कीजिये कि जंतर मंतर आंदोलन के संदर्भ में ही एक हिंदुत्व विचारक और केरल भाजपा के बौद्धिक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रमुख टीजी मोहनदास ने कहा था कि अगर स्थिति उनके नियंत्रण में होती, तो वे नई दिल्ली के आंदोलन स्थल के आसपास कर्फ़्यू लगाकर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवा देत। इस व्यक्ति ने प्रदर्शन में शामिल धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी विचारधारा वाली छात्राओं व महिलाओं के साथ रेप करवाने जैसी बेहद अमर्यादित और आपत्तिजनक टिप्पणियां भी की थीं। साथ ही गोदी मीडिया के नाम से बदनाम सत्ता का पिछलग्गू मीडिया भी जो जंतर मंतर आंदोलन से या तो मुंह मोड़े हुआ था या इसी आंदोलन विरोधी वर्ग की तरह आंदोलन में केवल नकारात्मकता तलाश रहा था,जिसे संसद भवन के पास चल रहा इतना बड़ा छात्र आंदोलन नजर नहीं आ रहा था वही मीडिया रांची में डेरा जमाये हुये है और अपने तरीके से छात्र आंदोलन का नरेटिव सेट करने में लगा है। इस दोहरेपन का केवल एक ही कारण है कि दिल्ली में केंद्र व दिल्ली राज्य, दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जबकि झारखण्ड में झारखंड मुक्ति मोर्चा , कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल, के गठबंधन यानी इण्डिया गठबंधन की सरकार है और झामुमो के हेमंत सोरेन इस सरकार के मुख्यमंत्री हैं। इसलिये इनका समर्थन छात्र आंदोलन को नहीं बल्कि यह झारखण्ड में इण्डिया गठबंधन की सरकार का विरोध कर रहे हैं। इस अवसरवादी विचारधारा का विरोध करने वालों का चेहरा रांची में उस समय भी बेनकाब हुआ जबकि जंतर मंतर के आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और वहां अनशन पर बैठने वाली अखिल भारतीय छात्र संगठन अकरअ की केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा जब हजारों छात्रों के साथ विधानसभा के लिये मार्च निकाल रही थीं उस समय एक युवक ने नेहा पर स्याही फेंक कर छात्र आंदोलन को समर्थन देने की अपनी हकीकत को उजागर कर दिया।

15 अगस्त, 2026

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

15 अगस्त, 2026 के पावन पर्व पर

आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा

नगरवासियों का हार्दिक अभिनन्दन व आग्रह करता है।

1. नगर पालिका परिषद के करों, शुल्कों व अन्य देयों का नियमित भुगतान करें।
2. जल ही जीवन है, उसे बर्बाद एवं दूषित न करें, नलों को खुला न छोड़ें।
3. जन्म-मृत्यु पंजीकरण 21 दिन के अन्दर करायें।
4. पालिका की भूमि / सम्पत्ति पर स्थाई / अस्थाई अतिक्रमण न करें।
5. सफाईकर्मी के आने से पूर्व ही अपने घरों का कूड़ा आदि निर्धारित स्थान पर ही डालें, ताकि सफाई कार्य में सहयोग मिल सके। सड़कों, नालियों एवं रास्तों पर कूड़ा-कचरा न डालें।
6. भवन निर्माण से पूर्व भवन मानचित्र की स्वीकृति अवश्य करायें।
7. नगर आपका है, इसे साफ-सुथरा रखने में नगर पालिका का सहयोग करें।
8. डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन में नगर पालिका का सहयोग करें, गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग डस्टबिन में डालें।
9. आपका नगर स्वच्छ सर्वेक्षण 2026 में भाग ले रहा है। इसे नम्बर 1 बनाने में सहयोग करें।

स्वच्छ सर्वेक्षण 2026

स्वच्छ नगर - सुंदर नगर

हमारा संकल्प, हमारा नगर

अब्दुल वहिद
अध्यक्ष
आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा
जिला बहराइच

रंग बहादुर सिंह
अधिशासी अधिकारी
आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा
जिला बहराइच

आदर्श नगर पालिका परिषद नानपारा, जिला बहराइच (उ.प्र.)

स्वच्छ उसका स्वस्थ उसका सुंदर उसका

कार्यालय नगर पंचायत उसका बाजार-सिद्धार्थनगर

माननीय योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश

मा0 श्यामधनी राही
विधायक, कपिलवस्तु

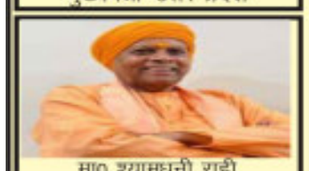

मा0 ध्रुव कुमार त्रिपाठी –
विधान परिषद सदस्य

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

नगर पंचायत उसका बाजार की ओर से समस्त नगरवासियों को स्वतंत्रता दिवस २०२६ की हार्दिक शुभकामनायें।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत सरकार

माननीय अरविन्द कुमार शर्मा
नगर विकास मंत्री

माननीय जगदम्बिका पाल
सांसद डुमरियागंज

मा0 सुभाष यदुवंश– एमएलसी

नगर वासियों से विनम्र अपील

- खुले में शौच कदापि न करें। खुले में शौच करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने से दंडित किये जायेंगे।
- वार्ड की स्वच्छ वातावरण प्रोत्साहन समिति में सक्रिय सहयोग कर वार्ड में पूर्ण स्वच्छता लायें।
- डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन में अपना सहयोग अवश्य करें एवं सूखा कूड़ा व गीला कूड़ा अलग करके कचरा संग्राहक को सौंपें।
- पर्यावरण को प्लास्टिक के प्रदूषण से मुक्त बनायें। पालीथीन का प्रयोग करते हुए पकड़े जाने पर जुर्माने से दंडित किये जायेंगे।
- कूड़ा–करकट आदि नालियों, सड़कों, खुले स्थानों में न फेंके, सफाई में सहयोग करें।
- बिना भवन का नक्शा पास कराये, भवन निर्माण न करायें।
- जल ही जीवन है इसकी बचत करें और भूगर्भ जलस्तर को बनाये रखने में अपना सहयोग करें।
- नगर पंचायत की भूमि, सार्वजनिक स्थलों, सड़क की पटरी, नाली / नालों आदि पर अवैध अतिक्रमण ना करें।
- पथ प्रकाश बिंदुओं को क्षति ना पहुंचायें।
- यह नगर आपका है इसे स्वच्छ एवं अपना सुन्दर बनाने में अपना सहयोग करें।

हेमन्त कुमार जायसवाल
अध्यक्ष प्रतिनिधि
नगर पंचायत उसका बाजार
सिद्धार्थनगर

मंजू जायसवाल
अध्यक्ष
नगर पंचायत उसका बाजार
सिद्धार्थनगर

सम्मानित सदस्य का नाम
श्रीमती प्रमिला देवी, श्री कन्हैया प्रसाद, श्री कासिम, श्रीमती कांती देवी,
श्रीमती सूर्यमती देवी, श्री विभूति प्रसाद अग्रहरि, श्री राजेश कुमार, श्री अंगद सहानी, श्री मयंक पाण्डेय,
श्री उपेन्द्रनाथ दूबे, श्रीमती पूनम त्रिपाठी, श्री अयोध्या साहू, श्रीमती प्रेमा देवी, श्री सूरज कुमार।
नामित सदस्यगण का नाम
श्री पवन जायसवाल, श्री दिलीप सिंह, श्रीमती सावित्री गौड़।

स्वतंत्रता दिवस

की हार्दिक शुभकामनाएँ

15 अगस्त 2026 के पावन अवसर पर

नानपारा विधानसभा क्षेत्र के समस्त नगरवासियों, ग्रामवासियों, माताओं-बहनों, बुजुर्गों, युवाओं एवं प्रिय बच्चों को

स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।

1. यह गौरवपूर्ण दिवस हमें उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तपस्या और बलिदान की याद दिलाता है, जिनके संघर्ष के कारण आज हम स्वतंत्र भारत में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं।
2. आइए, इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर राष्ट्र की एकता, अखंडता, भाईचारे और सामाजिक सौहार्द को मजबूत करने का संकल्प लें। अपने नगर और ग्रामों को स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित एवं विकसित बनाने में अपना योगदान दें तथा देशहित को सदैव सर्वोपरि रखें।
3. मेरा संकल्प है—नानपारा विधानसभा का प्रत्येक नगर, प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक परिवार विकास की मुख्यधारा से जुड़े, हर नागरिक को सम्मान मिले और हमारा क्षेत्र निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़े।
4. आइए, स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर हम तिरंगे की शान और भारत माता के सम्मान को सदैव ऊँचा रखने का संकल्प लें।

जय हिंद! जय भारत!

आपका अपना

रामनिवास वर्मा

विधायक — नानपारा विधानसभा क्षेत्र (283)

रामनिवास वर्मा
विधायक — नानपारा विधानसभा क्षेत्र (283)

हरिहरे वर्मा अपना दल (एस) विधायक प्रतिनिधि
बलहा नानपारा जिला बहराइच

कार्यालय नगर पालिका परिषद पडरौना, जनपद-कुशीनगर

स्वच्छ भारत

एक कदम स्वच्छता की ओर

15 अगस्त 2026

स्वतंत्रता दिवस

के पावन पर्व पर

नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाऐं

माननीय नरेन्द्र मोदी जी
प्रधानमंत्री भारत सरकार

माननीय योगी आदित्यनाथ जी
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार

अति प्रसन्नता के साथ आपको सूचित करना है कि 15 अगस्त 2026 को शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा देश की आजादी के 80वें वर्ष को आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। आजादी के इस महोत्सव के अवसर पर "हर घर तिरंगा" अभियान में भाग लेकर अपने घर तिरंगा फहरायें व जन आन्दोलन में सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करें। आजादी के इस अमृत महोत्सव व 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 के पावन पर्वा पर नगर के गणमान्य लोगों के साथ कायारोइण / अमर जवान शहीदों को पुष्पांजलि / महापुरूषों के प्रतिमाओं पर माल्यार्पण एवं राष्ट्रगान के साथ आएए हम सब मिलकर एक साथ एक संकल्प राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें।

"हर घर तिरंगा" कार्यक्रम की अवधारणा देश की स्वतंत्रता व प्रगति यात्रा को याद दिलाते हुए भारत के मिट्टी के लिए जन–जन के हृदय में देश प्रेम की भावना जागृत कराना और हमारी माटी में बसे वीरता के भाव को दर्शित कराना जायेगा।

आम जनता से अपील

- नगर क्षेत्र के अन्तर्गत आयोजित होने वाले "हर घर तिरंगा" कार्यक्रम को सफल बनाते तथा अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज सम्मानपूर्वक फहराया जाना सुनिश्चित करें।
- जन्म एवं मृत्यु की सूचना 21 दिन के अन्दर अनिवाइन दर्ज करायें।
- नगर को स्वच्छ बनाने में आप अपना सहयोग प्रदान करें।
- नगर पालिका परिषद पड़रौना में चल रहे विकास कार्यों में सहयोग प्रदान करें।
- नगर पालिका परिषद् पड़रौना द्वारा संचालित हस्ततीम महन्थ अभिनाथ जी महाराज पुस्तकालब / वाबतालब का उपयोग करें।
- 15 जुन्वर्र 2018 से सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह प्रतिबध्धित कर दिया गया है। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल न करें, प्रयोम करते हुए पाये जाने पर जुर्माना लगाया जायेगा।
- नगर पालिका परिषद् पड़रौना के समस्त बकाया करों की अदायगी समय से करें।

अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद पड़रौना–कुशीनगर	अध्यक्ष नगर पालिका परिषद पड़रौना–कुशीनगर	एवं माननीय सभासदगण

रेखा देवी	मालती	विश्वनाथ प्रसाद सिंह	संजय	क्यामुद्दीन	बलवन्त
अंगू देवी	बैमुद्दीन	उमा	अंशू	प्रवीण	कमलावती
तबददुम जहां	गीता	गीता	सौरभ कुमार सिंह	अमानतुल्लाह	प्रमोद कुमार श्रीवास्तव
एसलाबुल्लाह	संतोष	उत्तम कुमार चौहान	शहनाज	अभिनाश	शारदा
नामित सभासदगण:	धीरज पाठक	कुंज बिहारी चौरसिया	प्रमोद साहा	मनीषा साहनी	मुन्नी निषाद

सौजन्य से

विनय जायसवाल

नगर पालिका परिषद् पडरौना

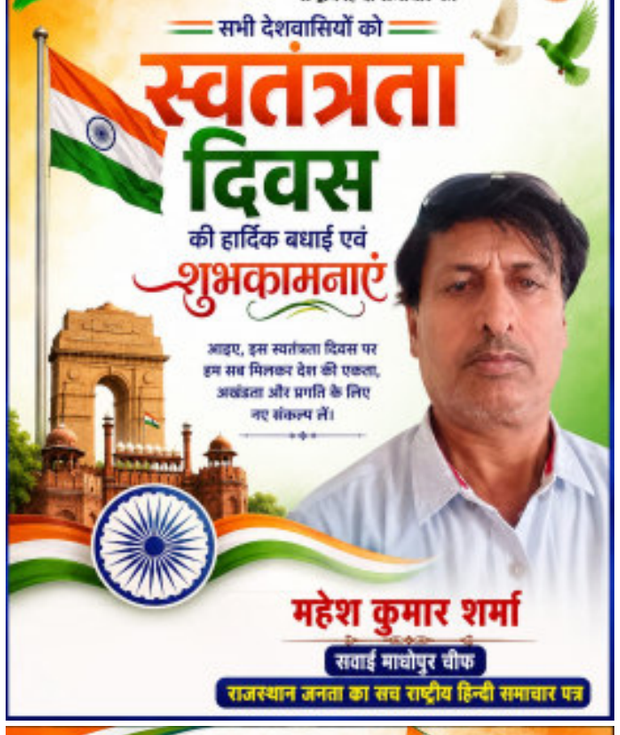

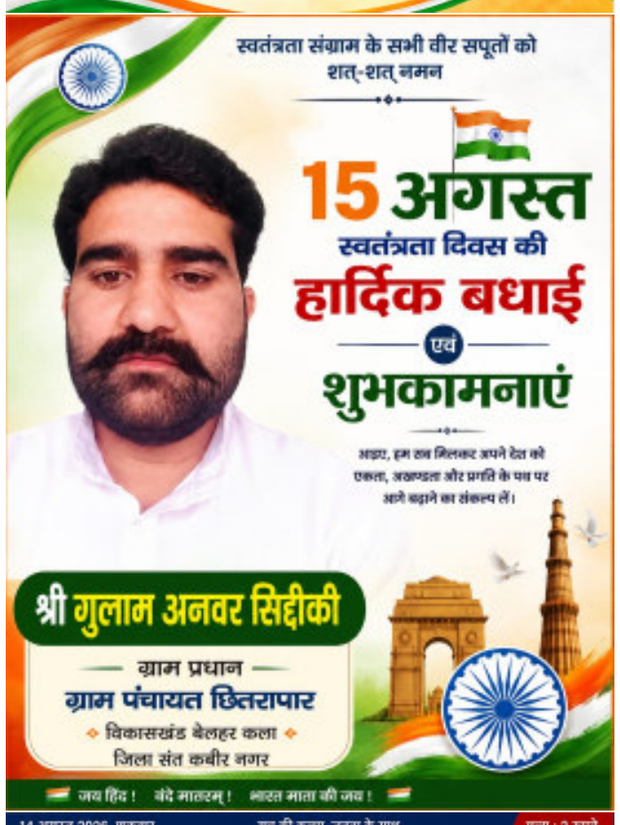

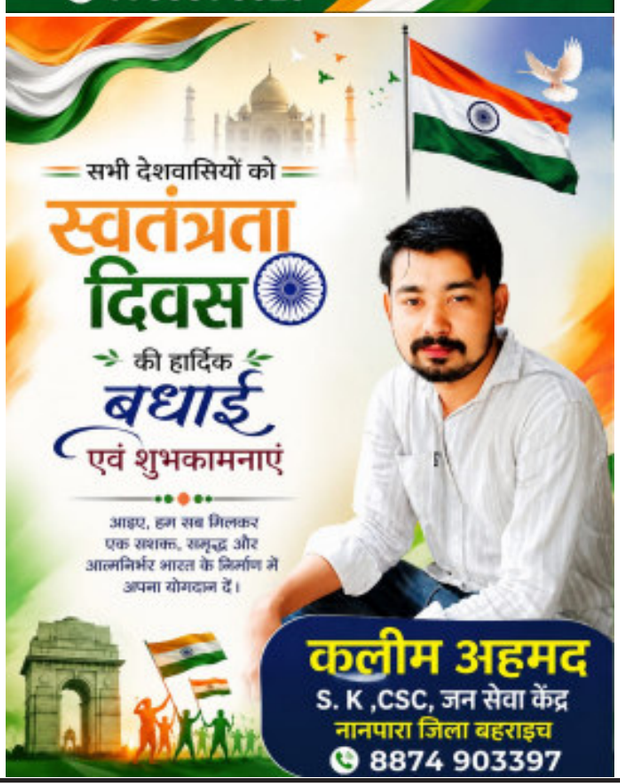

डॉ. शक्ति सिंह साधू (प्रधान सम्पादक), डॉ. प्रवीण (प्रबंध सम्पादक), एडवोकेट शैलेन्द्र श्रीवास्तव (कानूनी सलाहकार), राकेश अग्रवाल (जिला ब्यूरो उत्तर प्रदेश) अब्दुल नासिर स्टेट ब्यूरो उत्तर प्रदेश

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक शक्ति सिंह द्वारा राज तरूण आफसेट, एल0जी0एफ0 5–14, अंसल सिटी सेंटर, हजरतगंज, लखनऊ– 226001 से मुद्रित तथा 486/238–डी, डालीगंज, निरालानगर, जनपद लखनऊ–226020 से प्रकाशित।

सम्पादक– शक्ति सिंह मो0 7052608007 नोटः समाचार पत्र से संबंधित समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय होगा।